Amit shah speech Hindi Transcription

मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद में मेरे साथी, भाई बी एल वर्मा जी, इंटरनेशनल कॉपरेटिव एलायंस ग्लोबल के अध्यक्ष डॉक्टर वार्को जी, मंच पर उपस्थित सभी का नाम उल्लेख करना चाहिये, इस प्रकार के विशिष्ट योगदान वाले बैठे हुए महानुभाव, मैं इसलिये नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, कि समय काफ़ी गया है, मगर इन सब संस्थाओं के जो अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं, इन्होंने देश के सहकारिता आंदोलन को यहां तक इस मक़ाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए इक्कीस सौ ज़्यादा सहकारिता आंदालन के सभी नेता, सभी सरकारी बंधुओं, बहनों और देश भर में कई जगह ऑनलाइन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी सरकारी क्षेत्र के भाईयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी पंडित दीन दयाल जी की जयंती से करना चाहूंगा। क्योंकि मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का, सहकार में आने की प्रेरणा का मूल स्थान, दीन दयाल जी की अंत्योदय की नीति है। ग़रीब कल्याण और अंत्योदय उसकी कल्पना सहकारिता के अलावा हो ही नहीं सकती। पर देश में सबसे पहले, विकास की जब बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की, वो पंडित दीन दयाल जी थे, आज उनका जन्मदिन है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ो कार्यकर्ताओं के लिये, ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। उसी दिन ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। मित्रों सबसे पहले आज़ादी के पछत्तर साल के बाद, और ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया, इसलिये एक सहकारी कार्यकर्ता भी और आप सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, सहकारिता आंदोलन का जो अनुमोदन जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सब इसके लिये ताली बजा कर इसका स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं फिर से एक बार, देश भर के करोड़ों सहकारिता के कार्यकर्ताओं की ओर से, सहकारिता के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी ओर से एक विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रूचि का जो विषय है, देश में सबसे पहला, सहकारी मंत्री बनने का मौक़ा उन्होंने मुझे दिया है, मेरे लिये बहुत गौरव की बात है। आज जब हम यहां खड़े हैं, और एक नई शुरूआत सहकारिता आंदोलन को बल देने की, गति देने की, दिशा देने की, शुरू होने जा रही है उस वक़्त मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय की स्थापनी की है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर क सहकारिता के नेताओं को, और कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, कि नेगलेक्शन का टाइम समाप्त हुआ

है, और प्रीऑयरटी का टाइम शुरू हुआ है, आइये सब साथ में रह कर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर, सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, देश के विकास के अंदर, सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर, और आयामों तक अभी हमें पहुंचना बाक़ी है। हमें इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमें अपने काम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, काम के अंदर शिष्ट लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी, और काम के अंदर सहकारिता की भावना को, स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह, घुल मिल कर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। देश के करोड़ों किसान वंचित, पिछड़े, दलित, ग़रीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल, सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। कई लोग सहकारिता की प्रासांगिकता पर सवाल उठाते हैं, उनको लगता है कि सहकारिता आंदोलन अब इररेलीवेंट हो गया है। मैं बहुत मन से और बहुत सक्षमता के साथ कहना चाहता हूं, कि सहकारिता आंदोलन जो सबसे ज़्यादा कभी प्रासांगिक था तो अभी है, और बहुत बड़ी मंज़िल तक पहुंचना अभी बाक़ी है। हर गांव को कॉपरेटिव के साथ जोड़कर, सहकार से समृद्धि इस मंत्र से हर गांव को समृद्ध बनाना, और समृद्ध गांव के सम्पुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकारिता आंदोलन की भूमिका होगी। सहकारिता शब्द सह और कार्य इन दो शब्दों से मिल कर बना है। मिलजुल कर एक लक्ष्य के साथ, भातृबल से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। और हो सकता है मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि देश के करोड़ों लोगों की हम सब की इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की ताक़त बहुत कम होगी, आर्थिक ताक़त भी शायद हमारी कम होगी, मगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है, अगर इसको हम कॉपरेटिव के माध्यम से इकटठा करते हैं, तो एक प्रचंड ताक़त की निर्मिति होती है, जिसको कोई हरा नहीं सकता। और इसी आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन की एक नई शुरूआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिये ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगा देगा। और मित्रों, हमारी सहकारिता से जो ताक़त बनती है, वो ताक़त देश को समृद्ध करने की दिशा में काम आएगी, इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा, और एक नई सामाजिक पूंजी का कॉनसेप्ट भी खड़ा करेगा। पूंजी की दुनिया भर में कई वियाख्याएं हैं। मगर हम दस हज़ार से जीने वाले लोग हैं। दस हज़ार साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कॉन्सेप्ट,

सामाजिक पूंजी का विचार, और सामाजिक पूंजी का संस्कार, हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। कई देशों में सहकारिता क़ानून से अस्तित्व में आती है, कई देशों में सहकारिता, छोटे छोटे पैक्टस और बाक़ी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिये ज़रूरी ही है। भारत की जनता के स्वभाव में, सहकारिता घुल मिल गई है। इसके संस्कार में सहकारिता है, ये कोई उधार लिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे काम से स्वतः प्रकट हुआ, सहकारिता कॉन्सेप्ट है, इसलिये भारत में सहकारिता आंदोलन, कभी भी इररेलीवेंट नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बहुत समय से, लगभग पच्चीस साल से, सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। छोटी से छोटी इकाई से लेकर राज्य की बड़ी इकाइयों तक मैंने काम किया है। मैंने देखा है, कई सारे संकट आते हैं, सरकारें सर्कुलर निकालती हैं, परिपत्र निकालती हैं, परिपत्र की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मगर हमारी सहकारिता आंदोलन वाले, कोई परिपत्र की राह नहीं देखते, बाढ़ आती है तो गांव की पैक्ट वहां खड़ी हो जाती है और सबको खाना खिलाने का काम करती है। उनको आसरा देने का काम करती है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कॉपरेटिव बैंक, कितना मुनाफ़ा ख़र्च हो जाएगा इसका चिंता नहीं करता, डिविडेंड कितना कम हो जाएगा इसकी चिंता नहीं करता, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे अकाल हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे बारिश ज़्यादा आई हो या बाढ़ हो, वहां काम के लिये एक मुश्त होकर सब खड़े हो जाते हैं। सहकारी आंदोलन ने इस देश को, ढ़ेर सारे संकटों में, यहां पर बाहर निकालने के लिये अपना योगदान दिया है। सहकारिता भारत के लिये नई नहीं है। उन्नीस सौ चार से लेकर आज तक, भारत में सहकारिता ने ढ़ेर सारे मक़ाम देखे हैं। बहुत चढ़ाई उंचाई को भी हमने देखा है। कभी हम गिरे कभी हम संभले कभी आगे बढ़े, कभी तेज़ी से आगे बढ़े कभी धीरे हुए, परंतु ये गति कभी नहीं रूकी। और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, कि ये गति नहीं रूकनी चाहिये। आज इस अवसर पर, मैं सहकारिता आंदोलन को बल देने वाले, माधवराव गुड़बुले, वैकुम भाई मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, विटठल राव विखे पाटिल, यश्वंत राव चहवाण, धर्मेंद्र राव गाडगिल, और लक्षमण राव इनामदार जैसे कई लोगों को मैं याद करता हूं। और उन्हें प्रणाम कर के उनके आशीर्वाद से इस आंदोलन को एक नई गति देने के लिये हम आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। मित्रों आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं, पत्रकार भी मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी मिलते हैं। और साफ़ अर्थ में मुझे पूछते हैं, कि सहकारी आंदोलन रेलिवेंट है क्या ? उसकी प्रासांगिकता आज भी बनी हुई है क्या? मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की कुछ गुड प्रेक्टिसेज़ के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं। मैं अमूल की बात करना चाहता हूं,

अमूल का जन्म सरदार पटेल कर दूर दृष्टि स हुआ था। 1946 में अंग्रेज़ों ने एक फ़ैसला किया, कि किसानों को फ़रज़ी रूप से अपना सारा दूध एक अंग्रेज़ी कंपनी को देना पड़ेगा। इसके ख़िलाफ़ एक आंदोलन हुआ, खेड़ा ज़िले के अंदर, सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को कहा, कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते, तब तक इसके ख़िलाफ़ दूध का आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। और वहां एक शुरूआत हुई, अमूल की, सरदार पटेल के मार्गदर्शन में भाई त्रिभुवन ने दो ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियों का पंजीकरण करवाया, जिसमें अस्सी किसान जुड़े सिर्फ़ अस्सी किसान। और वो अमूल आज कहां है। दो हज़ार बीस इक्कीस में इसका टर्नओवर तिरेपन हज़ार करोड़ को पार कर गया है। एक दिन में लगभग तीस मिलियन दूध का प्रबंधन ये हमारा कॉपरेटिव संस्थान करता है। इससे छत्तीस लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं। और विशेषकर महिलाओं को एम्पॉवर करने का काम किया है, मैंने तो गांव में देखा ह, गुजरात में शनिवार को जब महिला के हाथ में अपना चेक आता है, और जब उसके हाथ में कैश आता है तो उसे देखकर मन के बहुत अंदर तक शांति मिलती है। 36 लाख किसान परिवारों को, अमूल आज अपने साथ जोड़े हुए है। 18 ज़िलों का ये फ़ेडरेशन है, 87 से ज़्यादा डेरी के मैनूफ़ैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं, और उसकी प्रबंधन क्षमता, 39 मिलियन की प्रबंधन क्षमता आज है। उसकी क्षमता आज 39 मिलियन टन दूध को प्रोसेस करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कॉरपोरेट डेरी जो नहीं कर सकती, ये हमारी अमूल ने कर के दिखाया है, और मैं मानता हूं यही उदाहरण लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिये। लिज्जत पापड़, बहुत कम लोगों को यहां भी कम ही मालूम होगा, कि लिज्जत पापड़ एक कॉपरेटिव है। 1959 में, जसवंती बेन पोपट नाम की एक गुजराती महिला साहसिक ने, अस्सी बहनों को साथ में लेकर एक कॉपरेटिव बनाकर पापड़ बनाने की शुरूआत की थी। 2019 में उनका कारोबार, सोलह करोड़ से ज़्यादा का कारोबार था, और अस्सी करोड़ के पापड़ निर्यात करती हैं। 45 हज़ार महिलाएं लिज्जत के कॉपरेटिव से जुड़ी हैं। और ये सक्सेज़ स्टोरी देश भर की महिलाओं के लिये परणा का एक स्रोत हैं। अमूल और लिज्जत दोनों आज सफल हैं। तो देश की महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दूध भरने में भी और पापड़ बनाने में भी। इफ़को, जो आज हमारे यजमान बैठे हैं, चेयरमेन साहब भी बैठे हैं और एम डी अवस्थी भी बैठे हैं, इफ़को ने इस देश की हरित क्रांति को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कोपरेटिव्ज़ के साथ, एक इस्पेसीफ़ाई सोसायटी बनी, और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज 36 हज़ार से ज़्यादा, कॉपरेटिव को मिम्बर बना कर, लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उसका लाभांश पहुंचाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी अगर कुछ कमाएगी, तो उसका सबसे

बड़ा हिस्सा उसके मालिक के पास जाएगा, और इफ़को जो कुछ भी कमाएगी, इसकी पाई पाई साढ़े पांच करोड़ किसानों के घर में जाएगा। इसी को कॉपरेटिव कहते हैं। आज इफ़को ने लगभग देश के, उर्वरक की पूरी ज़िम्मेदारी दो तीन सौ और कॉपरेटिव को साथ में रख कर उठाई है। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, चेयरमेन साहब और एमडी जी का, अवस्थी का, कि इन्होंने नैनो टैक्नोलॉजी को ज़मीन पर उतार कर, बहुत बड़ा काम किया है। और इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है, कि इन कॉपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से ही, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि उर्वरक खाद इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और हमारे उर्वरक हमारे देश में ही काम आएंगे। इसी तरह से क्रिप्को, क्रिप्को भी लगभग, 9 हज़ार 5 सौ समितियों का बना हुआ, एक संघ है, उसकी मूढ़ी लगभग तीन सौ अठासी करोड़ है। शेयरधारकों को एक साल में, इक्कीस सौ अठारा करोड़ का लाभांश क्रिपको ने दिया है आप इससे कल्पना कीजिये। ये सब सक्सेज़ स्टोरी हैं। और इतना ही नहीं है, बहुत लंबी सूचि है, नेफ़ेड है, मैं मणिपुर गया था, रेणु हथकरघा हस्त शिल्प, 70 साल से एक लय के साथ वो कॉपरेटिव में अपना योगदान करता है। 1925 से चलती हुई, उरूंगल श्रमबंध सहकारी समिति, केरल, टोटामार्ता सहकारी संघ द्रावणगिरी कर्नाटक, कोजीकोड ज़िला सहकारी हॉस्पिटल ढ़ेर सारी चीज़ें हैं, जिन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से कैसे छोटे छोटे लोगों से पूंजी इकटठा कर के देश के अर्थतंत्र और देश के विकास इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, और सभी मुनाफ़ा सभी छोटे छोटे घरों में कैसे जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, गुजरात लगभग सारे संस्थानों के कर्ता धर्ता यहीं पर हैं, वो निर्देशक हैं चेयरमेन हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं, कि हमें काफ़ी कुछ करना बाक़ी हैं, क्या बीज संस्करण में, हमारी ये सफल कॉपरेटिव अपना योगदान नहीं दे सकतो हैं क्या, अच्छे बीज क्यों विदेश से लाने पड़ेंगे, बीज के क्षेत्र में हम, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, क्या कोई कॉपरेटिव चैलेंज एक्सेप्ट कर के किसानों की उपज को निर्यात करके ट्रेडिंग हाउज़ नहीं बन सकती है क्या? जिसके माध्यम से छोटी छोटी मंडियां, अपनी उपज को विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें, निश्चित बन सकती हैं। फूड प्रोसेसिंग का दुनिया भर में बाज़ार पड़ा है, छोटा किसान नहीं कर पाएगा ? और किसी को रूचि भी नहीं है, और करेगा तो भी किसान वहीं का वहीं रह जाएगा, अगर ये हमारे सफल कॉपरेटिव, एक एक क्षेत्र को पकड़ कर एक्सपेंशन का काम करें, तो मुझे विश्वास है कि पांच साल के अंदर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, जहां कॉपरेटिव की फ़ैक्ट्री नहीं होगी, और सहकारिता मंत्रालय, इसीलिये बनाया है कॉपरेटिव को मज़बूत करना है, कॉपरेटिव का व्यास बढ़ाना है, कॉपरेटिव के अंदर पारदर्शिता

लानी है। कॉपरेटिव संस्थाओं को मॉर्डनाइज़ करना है, कंप्यूटराइज़ करना है। और ये स्पर्धा में टिक जाए इस प्रकार की स्पर्धा में टिकने वाली सफल कॉपरेटिव बनाना है। ये सारी चीज़ों को करने के लिये ही, ये कॉपरेटिव मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। मित्रों आज मं इसलिये आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सब लोग कॉपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मगर जामवंत ने हनुमान जी को नहीं कहा, कि हनुमान जी आप रामेशवरम से लंका तक समुंद्र लांघ सकते हो, उनको विश्वास नहीं था। जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो, तुम समुंद्र लांघ सकते हो तो हनुमान जी कूदे और समुद्र लांघ गए। मैं आपको क्या बताउंगा कि कॉपरेटिव क्या है आप सब मुझसे ज़्यादा कॉपरेटर हैं। परंतु मैं आज कुछ चीज़ें इसलिये बताना चाहता हूं, जिससे हमारी स्टेंथ से हम परिचित हो जाएं। मित्रों लगभग 91 प्रतिशत गांव ऐसे हैं, जहां छोटी बड़ी कोई ना कोई कॉपरेटिव संस्था काम करती है। दुनिया का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां 91 प्रतिशत गांवों में कॉपरेटिव संस्थाएं काम करती हों। सहकारी समितियों की संख्या आठ लाख पचपन हज़ार से ज़्यादा रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं। लगभग साढ़े आठ लाख से ज़्यादा केडिट कॉपरेटिव सोसायटी हैं। लोन ना देने वाली सहकारी समितियां साठ लाख से ज़्यादा हैं। राष्ट्रीय सहकारी संघ 17 से ज़्यादा हैं। राज्यस्तरीय सहकारी बैंक, 33 हैं, ज़िला स्तरीय सहकारी बैंक 363 हैं। और लगभग 95 हजार में से 63 हज़ार पैक्टस काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से देखें तो हर दसवें गांव में एक पैक्स काम कर रहा है। मैं आगे बताउंगा कि ये संतोषजनक स्थिति नहीं है। मगर हर दसवें गांव में एक पैक्स होना दुनिया के सहकारिता के आंकड़ों को जब अभ्यास करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पैक्स ही माध्यम है किसान का कल्याण करने का। ये पैक्स ही माध्यम है कि जो सरकार कम ब्याज पर लोन देती है किसान को उसको पारदर्शी तरीक़े से उस तक पहुंचाने का। पैक्स ही माध्यम है उसको खेती के लिये उपयोगी चीज़ों को उस तक पहुंचाने का। पैक्स को मज़बूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये। मैं अंत में पैक्स पर बात करूंगा। और प्रतिशत में अगर मैं योगदान बताना चाहूं तो कृषि श्रृण वितरण का 29 प्रतिशत वो कॉपरेटिव व्यवस्था से जाता है। उरर्वक वितरण 35 प्रतिशत कॉपरेटिव करता है। उर्वरक का उत्पादन खाद का उत्पादन, वो भी लगभग तीस प्रतिशत करता है। देश की कुल चीनी का उत्पादन 31 प्रतिशत सहकारी चीनी मिलें करती हैं। तकलिसपिंडल 29 प्रतिशत, दूध की ख़रीदारी 20 प्रतिशत, गेहूं की ख़रीदारी 13 परसेंट कॉपरेटिव करती हैं। धान की ख़रीदारी बीस परसेंट करती हैं। और मछवारे के क्षेत्र में भी कॉपरेटिव का योगदान 21 परसेंट है। मैं इसलिये आंकड़े कहता हैं दोस्तों कि बहुत मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म पर आज हम खड़े हैं। समय आ गया है कि नए लक्ष्य तय करना और नए लक्ष्यों को सिद्ध करने

के लिये हम आगे बढ़ें। ये प्लेटफ़ॉर्म जो हमारे पुरखों ने भारत की कॉपरेटिव आंदोलन के पुरखों ने हमें दिया है उस प्लेटफ़ॉर्म पर एक मज़बूत बहुमंज़िला इमारत बनाने का काम यहां हॉल में बैठे हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी सहकारी लोगों को करना है। और इसीलिये मोदी जी ने ये सहकारिता आंदोलन का गति देने के लिये सहकारिता मंत्रालय की रचना की। हमारी सफलता चार ही चीज़ों पर निर्भर हो सकती है। संकल्प शक्ति साफ़ नियत और परिश्रम और संघ भाव से काम करना। ये चार मूल सिद्धांत हैं अगर हमसब इसको कॉपरेटिव के अंदर स्प्रिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है उसका उददेश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की ज़िम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की है। और इसका एक स्वदेशी यंत्रणा बनाने की ज़िम्मेदारी भी सहकारिता मंत्रालय की है। मित्रों कृषि क्षेत्र में सात साल में मोदी जी अमूल चूल परिवर्तन ले कर आए हैं। मैं सिर्फ़ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009 – 2010 में कृषि बजट बारह हज़ार करोड़ था मैं फिर से बताता हूं बारह हज़ार करोड़। बारह हज़ार करोड़ बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 2020– 21 में इस बजट को बढ़ा कर एक लाख चौंतीस हज़ार चार सौ निनयानवे करोड़ कर दिया। मैं इसलिये बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बग़ैर संभव नहीं है। हमने ढ़ेर सारे किसानों को सपोर्ट करने की बात कही, स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे, कि किसानों की आए बढ़नी चाहिये, लागत से पचास प्रतिशत से ज़्यादा होना चाहिये। कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज़्यादा एमएसपी तय कर के किसानों को पहली बार फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोड कर सकता हूं जिसके अंदर स्प्रिट थी, मगर होती नहीं थी। प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना, देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग एक लाख अटठावन हज़ार करोड़ रूप्या डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचाया गया। मित्रों स्टार्ट अप शुरू करने का एक नया अभियान चलाया है। दस हज़ार नए एफ़पीओ बनाए गए हैं। लगभग 68 सौ पैंसठ करोड़ रूप्या वित्त पोषण के लिये अलग से ख़र्च किया जाना है। नई मंडी की योजना लाए हैं, स्वायल हेल्थ कार्ड दिया है, और ये सारी चीज़ों के अंदर सहकारी क्षेत्र का पैक्स का एक रोल है। हमने सारी चीज़ों को पैक्स के अंदर, मज़बूती से इसका अध्ययन कर के इसकी इंपलीमेंटेशन एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरूआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें नीचे तक पहुंच पाएंगी। मित्रों सहकारी मंत्रालय का जो गठन किया है कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट

है मैं स्टेट और सेंटर के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, क़ानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारी मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर के चलेगा किसी के साथ संघर्ष करने के लिये नहीं बना है। इसलिये किसी के भी मन में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट है या सेंटर सब्जेक्ट है। हम मदद सब की कर सकते हैं, राज्यों की भी करेंगे सबको साथ में लेंगे, और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कार्य समितियों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम इस सहकारी मंत्रालय के तत्वाधान में होगा, बहु राज्य कॉपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिये हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिये एक बहुत बड़ी बात हुई, हमने तय किया है कि कुछ समय के अंदर ही नई सहकार नीति पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में, अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021 – 22 में, ये आज़ादी का पछत्तरवां साल है। हम इस महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की शुरूआत भी करेंगे। पैक्स को मज़बूत करना, 63 हज़ार पैक्स छे लाख गांवों के बीच में कम हैं, हम एक लक्ष्य रखेंगे कि आने वाले पांच साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए, पैक्स की संख्या को 65 हज़ार से बढ़ा कर तीन लाख तक पहुंचाने के लिये उचित क़ानून में ख़ाका बनाने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा। और वो एडवाइज़री होगा स्टेट के पास भेजेंगे, स्टेट अपने क़ानूनों में परिवर्तन करेगा, सबसे बड़ी दिक़्क़त ये है कि पैक्स बैंकरप हो जाता है जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप्त नहीं होता है, नया पैक्स बन नहीं सकता है। इसकी क़ानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो पैक्स को साइड में रखकर वाइंडिंग अप का काम शुरू हो जाए, नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ़ जाए, हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कंप्यूटराइज़ेशन समाप्त हो इसमें भारत सरकार भी अपना बड़ा योगदान देने वाली है, और सारे पैक्स का कंप्यूटराइज़ेशन करने के लिये बहुत कम समय में भारत सरकार योजना लेकर आएगी। मित्रों कंप्यूटराइज़ेशन के साथ साथ एक ऐसा सॉफ़्टवेयर बनाने की क़वायद भी शुरू की है जो पैक्स डीसीबी और नाबार्ड तीनों को जोड़ेगा एक ही सॉफ़्टवेयर से, अकाउंटिंग पैक्स की , डिस्ट्रिक्ट बैंक्स की और नाबार्ड की, एक लय के साथ होगी और स्वभाषा में होगी और स्थानीय भाषाओं में भी होगी, मित्रों पैक्स को एफ़पीओ बनाने के लिये भी, क्या किया जा सकता है, इस पर मेरा मंत्रालय काम कर रहा है, मेरा आग्रह है सहकारिता प्रशिक्षण पर, सहकारिता प्रशिक्षण को और पैना करना पड़ेगा, प्रोफ़ेशनल करना पड़ेगा, स्किल्ड डेवेलपमेंट के सारे एरिया जो सहकारिता को छूते हैं, वो सारे एरिया की स्किल्ड डेवेलपमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा कोरपोस होता है, मगर उसका उचित उपयोग

करना है मगर इसके लिये भी मेरा मंत्रालय एक कार्य योजना बना रहा है, क्रेडिट सोसायटियों की भूमिका, और मज़बूत और नीचे तक ले जाने की ज़रूरत है। जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्रेडिट मिल सके। दीपावली का त्यौहार है और हज़ार रूप्या किसी को चाहिये दीपावली मनाने के लिये, इनकम है मगर आज नहीं है क्योंकि दो महीने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको हज़ार रूप्या मिल जाए उसकी दीपावली अच्छी जाए इस प्रकार की क्रेडिट सोसायटी नीचे तक बननी चाहिये, ये कोई बैंक नहीं कर सकता, बैंक काग़ज मांगेंगे, अरे भई इसके पास कागज़ होते, तो हज़ार रूप्ये लेने को क्यों आता वो, काग़ज़ नहीं है। हमारी छोटी कॉपरेटिव सोसायटियां जो छोटे छोटे लोन देती है वो आंख की शर्म से देती है, और मैं मानता हूं, इसको हम नीचे तक मज़बूत करने का काम करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड में भी पैक्स की भूमिका कुछ राज्यों में अभी तक बनी नहीं है। इसको हम बनाने के लिये पूरा प्रयास करेंगे। प्रायरटी सेक्टर लेंडिंग, सिर्फ़ अल्पकालीन लोन नहीं है, सभी प्रायरटी सेक्टर लेंडिंग में कॉपरेटिव की भूमिका बढ़ाने के लिये सभी प्रायरटी सेक्टर लेंडिंग के भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ सहकारी मंत्रालय काम कर के ज़मीन पर प्रायरटी लेंडिंग सभी प्रकार के कॉपरेटिव के माध्यम से हो इसके लिये हम काम करेंगे। जैसे स्वसहायता यूथ। आज तक इस देश में स्वसहायता यूथों ने अपनी स्वसहायता सोसायटी नहीं बनाई। य अमूल जो है ना ये स्वसहायता यूथों का ही स्पेसीफ़ाई सोसायटी है। अमूल की तरह स्वसहायता यूथ हर राज्य में अपनी स्पेसीफ़ाई सोसायटी बनाकर छोटी छोटी स्वसहयता यूथों की बनाई हुई चीज़ों की मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिये भी एक विशेष क़ानूनी पबंधन करने की ज़रूरत है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, मछुआरा सहकारिता के लिये भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमारे पास है, इसका दोहन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते हैं। छोटे मछुआरों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें लेने का, ना नेट लेने को पैसे ना यांत्रिक बोट लेने का पैसा है तो मछुआरा कॉपरेटिव बनाकर, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देंगे ताकि इसका मुनाफ़ा सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये भी हमने काम किया है। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में भी जनजातीय सहकारिता, जो वन उत्पाद हैं उसके लिये भी कॉपरेटिव बनाकर, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। मित्रों बुनियादी ख़ाका, सहकारी समितियों का और देश भर के हर राज्य के क़ानून के अंदर, एक प्रकार की सिनर्जी हो, इस प्रकार का प्रयास भी हमने हाथ में लिया है। मुझ मालूम नहीं सफलता कितनी मिलेगी, मगर हमारा इरादा नेक है इसलिये विश्वास है कि इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, हम ज़रूर सफल होंगे, मगर आज इतने सारे सहकारिता आंदोलन के दिग्गज नेता आए हैं, ट्रेनिंग, स्किल डेवेलपमेंट,

पारदर्शिता, पारदर्शी भर्ती प्रकिया, और पारदर्शी चुनाव प्रकिया, और खुला सदस्य, सभासद बनाने का खुला कार्यकम, सहकारिता संस्थाओं को करना पड़ेगा, ट्रेनिंग, स्किल डेवेलपमेंट, पारदर्शिता, पारदर्शी भर्ती प्रकिया, और चुनाव प्रकिया में परदर्शिता इसे हमको लाना ही होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे वरना हम पोछे रह जाएंगे। और हम सबका ये दायित्व है, कि मोदी जी ने इस आंदोलन को गति देने के लिये, एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, और मोदी जी के इस निर्णय को सफल बनाने के लिये, और सहकारिता आंदोलन को एक दम गति के साथ आगे बढ़ाने के लिये हमने सहकारिता क्षेत्र के अंदर, जो आंतरिक परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उस पर भी आत्म निरीक्षण करके बल देना पड़ेगा, मित्रों सहकारिता कॉमन सर्विस सेंटर की कल्पना भी हमारा मंत्रालय कर रहा है, नेशनल डेटा बेस के लिये भी हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, और नेशनल कॉपरेटिव इनीशियेटिव बनाने के लिये भी, चार जगह से दरख़्वास्त मिली है, मुझे लगता है कि ये प्रोफ़ेशनल यूनीवरसिटी की जगह कोई कॉपरेटिव संस्थान आगे आए, तो अच्छा है, एक नेशनल कॉपरेटिव इनीशियेटिव बनाने की ज़रूरत है। कोई संस्थान अपनी दरख़्वास्त लेकर आए तो ज़रूर अच्छा काम हो सकता है। मित्रों दो तीन लोगों ने जैसे चंद्रभान जी ने और बाक़ी लोगों ने कुछ कुछ बातें दबे स्वरों में कही हैं, मैं उनको इतना कहता हूं, कि आप नो बोले होते तो भी चलता, बोलते तो भी अच्छा होता और मुखरकर बोलते तो भी अच्छा होता, मगर इन सारी चीज़ो की मुझे मालूमात है क्योंकि मैं आप में से ही हूं। अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स के प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स, भेदभाव पूर्ण रवैया, सरकार का पक्षपात, सरकारी कर्मचारियों का पक्षपात, इन सारी चीज़ों से मैं अवगत हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, इतना भरोसा रखिये। और इसीलिये मोदी जी ने सहकारिता को प्राथमिकता दी है, इसीलिये आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के अंदर, सहकारिता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है, और इसीलिये सहकार से समृद्धि का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया ह। क्योंकि हम चाहते हैं कि समग्र विकास होना चाहिये। विकास सर्वस्वपर्शीय होना चाहिये। विकास समाज समेवक होना चाहिये। विकास के मॉडल के अंदर, सबको छूने की ताक़त होनी चाहिये। और विकास का मॉडल, सबको समाहित करने की बाहें फैलाकर खड़ा हुआ मॉडल होना चाहिय। और वो कॉपरेटिव के अलावा संभव नहीं है। इसीलिये कॉपरेटिव मंत्रालय की रचना की गई। चीनी मिलों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई जगह हमारे त्रिस्तरीय एग्रीकल्चर फ़ाइनांस के ढांचे को डिस्टर्ब करने की बात हो रही है। मैं इन सबके बारे में अभी बहुत स्पष्टता से कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी विचार विमर्श चल रहा है सबसे चर्चा भी करना है। परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, कि आपकी समस्या आप

ज़रूर मुझे लिख कर भेजिये, छोटी से छोटी चिटठी को ध्यान से पढ़ कर मैं उस उचित निर्णय करूंगा, अगर लिखकर नहीं भेजेंगे तो भी मैं सामने से संपर्क कर और आपकी तकलीफ़ों को समझ कर उसके निवारण के लिये प्रोएक्टिव रहूंगा। और ये मोदी जी की इच्छा है देश के प्रधान मंत्री जी के मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रकिया में हिससेदार बनाना, सहकारिता के माध्यम से हर परिवार को समृद्ध बनाना, और हर समृद्ध हुए परिवार के समपुट से देश को समृद्ध बनाना यही सहकार से समृद्धि का मंत्र है। और हमें इसमें जी जान से लगना है। मैं यहां आया हूं, मेरा और मेरे साथी मंत्री जी का स्वागत किया, डॉक्टर साहब भी अर्जेनटीना से पधारे हैं यहां पर, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत का सहकारिता क्षेत्र और भारत का सहकारिता आंदोलन, देश भर में गुड प्रेक्टिसेज़ साझा करने का एक प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है। आप इनिशियटिव लेकर ऐसी कोई संस्था का भारत के अंदर कोई हेड क्वार्टर बनाइये, जो दुनिया भर के कॉपरेटिव के गुड प्रेक्टिसेज़ का माध्यम बने, हम आपका स्वागत करने के लिये यहां पर तैयार हैं, और फिर से एक बार कहता हूं, कि प्रधान मंत्री जी की मन की इच्छा ह कि सहकारिता के आधार पर भारत की अर्थ नीति के विकास का एक नया अध्याय लिखा जाए, मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को चरितार्थ करने के लिये सहकारी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका निभानी होगी, और सहकारिता को हमें संस्कार बनाना होगा। और जो महत्वपूर्ण भूमिका हम निभाएंगे, वो आने वाला देश आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, इसका मुझे विश्वास है। और देश भर से ऑनलाइन आंकड़ा जो संचालिका महोदया जी ने बताया मेरे खड़े होने से पहले सवा चार करोड़ लोग ऑनलाइन जुड़े थे, बहुत सारी समितियां भी जुड़ी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक भी जुड़े हैं, उन सभी सहकारिता आंदोलनकारियों को और आप सभी को बहुत बहुत मन से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और विश्वास दिलाता हूं, कि नई उर्जा के साथ सहकारिता आंदोलन को एक नए क़वायद भरने की जो शुरूआत मोदी जी ने की है हमसब साथ मिलकर इसको सफल बनाएंगे, वंदे मातरम भारत माता की जय।